Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM) - 2026 Investor Meet in Ahmedabad

The Rajasthan Government is proactively working towards positioning the state as an agricultural innovation and investment hub. As part of the Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)–2026, Rajasthan Agriculture Department will host an Investor Meet in Ahmedabad on 30 April. This will be a platform to explore investment, innovation and collaboration opportunities in the agriculture, agritech, dairy and cooperative sectors. It is significant for RAS because it showcases Rajasthan's initiatives to foster technology-driven agriculture, investment opportunities, nurturing startups and ensuring rural prosperity.

Key Highlights of the Investor Meet

- The Investor Meet will be held in Ahmedabad on 30 April under GRAM–2026.
- Chief Minister Bhajanlal Sharma will be the Chief Guest.
- Agriculture and Horticulture Minister Dr. Kirodi Lal and Animal Husbandry and Dairy Minister Joraram Kumawat will also be present.
- Rajasthan and Gujarat dignitaries will address the forum.
- Principal Secretary, Agriculture and Horticulture, Manju Rajpal, and Gujarat's Principal Secretary, Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department, Ramesh Chand Meena, will make presentations.

- A roadshow will provide a platform for policymakers, industry, investors, startups, dairy experts and cooperative sector experts.
- A special business-to-business meeting with investors will also be arranged.
- An interaction will be organised on “Opportunities and Investment Potential in Animal Husbandry, Dairy and Cooperatives.”

Event Goals

- To promote investment in Rajasthan's agriculture and agritech.
- To foster collaboration among government, industry, investors and startups.
- To promote animal husbandry, dairy and cooperatives.
- To promote technologically and innovatively driven farming.
- To build Rajasthan into an "investor-friendly" and "self-reliant" agricultural state.

Significance for Rajasthan

- The event can provide opportunities for agritech startups and investors.
- It may boost agricultural modernisation via innovation.
- It can help boost Rajasthan's dairy and cooperative movement.
- It may help the state to become an important national and international agritech hub.
- It may help promote rural development, diversification and generate employment.

RAS Exam Relevance

For RAS, this can be helpful in Rajasthan economy, agriculture, dairy sector, cooperative movement, investment promotion, innovation and state government initiatives. The event shows the government's role in modernising the agriculture sector and making it more market-friendly. It also reflects the efforts of Rajasthan to connect agriculture with startups, investment and cooperatives.

Conclusion

The GRAM-2026 Investor Meet in Ahmedabad is a significant initiative for the development of Rajasthan's agriculture. This event will bring together investors, startups, policymakers and experts to open up new opportunities for agriculture, agritech, dairy and cooperatives. It can help build Rajasthan as a robust, independent and innovative agritech hub.

MCQs

MCQ 1: Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)–2026 Investor Meet will be held in which city?

RASonly

a) Jaipur

b) Ahmedabad

c) Jodhpur

d) Udaipur

Answer: b) Ahmedabad

Explanation : The Investor Meet of Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM) - 2026 will be held in Ahmedabad on April 30. It will focus on the investment and partnership opportunities in the agriculture, agritech, dairy and cooperative sectors.

MCQ 2: Who will be the Chief Guest at the GRAM-2026 Investor Meet?

a) Dr. Kirodi Lal

b) Joraram Kumawat

c) Bhajanlal Sharma

d) Manju Rajpal

Answer: c) Bhajanlal Sharma

Explanation : Bhajanlal Sharma, the Chief Minister of Rajasthan, will be the Chief Guest at GRAM-2026 Investor Meet. The Chief Minister's presence at the event highlights the significance of the event for Rajasthan's agricultural innovation and investment.

MCQ 3: What will be the theme of the key panel discussion?

a) Heritage and tourism

b) City transportation and smart cities

c) Animal husbandry, dairy and cooperative development opportunities and investment

d) Solar parks

Answer : c) Opportunities and investment potential in animal husbandry, dairy and cooperatives

Explanation : The Investor Meet will include a panel discussion on opportunities and investment potential in animal husbandry, dairy and cooperatives. This is because Rajasthan wants to boost agriculture-related industries and create an investment-friendly rural environment.

RASonly

वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन (ग्राम)–2026 निवेशक बैठक, अहमदाबाद

राजस्थान सरकार राज्य को कृषि नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। **वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन (ग्राम)–2026** के तहत राजस्थान कृषि विभाग **30 अप्रैल को अहमदाबाद में निवेशक बैठक** आयोजित करेगा। यह बैठक कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, दुग्ध और सहकारिता क्षेत्रों में निवेश, नवाचार और सहयोग की संभावनाओं को तलाशने का मंच बनेगी। RAS के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तकनीक-आधारित कृषि, निवेश अवसरों, नव-उद्यमों के प्रोत्साहन और ग्रामीण समृद्धि के लिए राजस्थान की पहलों को दर्शाती है।

निवेशक बैठक की मुख्य विशेषताएँ

• निवेशक बैठक **ग्राम–2026** के तहत 30 अप्रैल को अहमदाबाद में आयोजित होगी।

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे।

• कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल और पशुपालन एवं दुग्ध मंत्री जोराराम कुमावत भी उपस्थित रहेंगे।

• राजस्थान और गुजरात के गणमान्य व्यक्ति इस मंच को संबोधित करेंगे।

• कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल तथा गुजरात के कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव रमेश चंद मीणा प्रस्तुति देंगे।

• एक प्रचार-प्रदर्शन कार्यक्रम नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, निवेशकों, नव-उद्यमों, दुग्ध विशेषज्ञों और सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञों को मंच प्रदान करेगा।

• निवेशकों के साथ विशेष व्यावसायिक बैठक भी आयोजित की जाएगी।

• **"पशुपालन, दुग्ध और सहकारिता में अवसर एवं निवेश संभावनाएँ"** विषय पर संवाद आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य

• राजस्थान के कृषि और कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।

• सरकार, उद्योग, निवेशकों और नव-उद्यमों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

• पशुपालन, दुग्ध और सहकारिता क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

• तकनीक और नवाचार आधारित खेती को प्रोत्साहित करना।

• राजस्थान को "निवेशक-अनुकूल" और "आत्मनिर्भर" कृषि राज्य के रूप में विकसित करना।

राजस्थान के लिए महत्व

• यह कार्यक्रम कृषि-प्रौद्योगिकी नव-उद्यमों और निवेशकों के लिए अवसर प्रदान कर सकता है।

RASonly

• यह नवाचार के माध्यम से कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।

• यह राजस्थान के दुग्ध और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

• यह राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि-प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने में सहायक हो सकता है।

• यह ग्रामीण विकास, विविधीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकता है।

RAS परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

RAS के लिए यह विषय राजस्थान अर्थव्यवस्था, कृषि, दुग्ध क्षेत्र, सहकारिता आंदोलन, निवेश संवर्धन, नवाचार और राज्य सरकार की पहलों के अंतर्गत उपयोगी हो सकता है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र को आधुनिक और बाजार-अनुकूल बनाने में सरकार की भूमिका को दर्शाता है। यह कृषि को नव-उद्यमों, निवेश और सहकारिता से जोड़ने के राजस्थान के प्रयासों को भी स्पष्ट करता है।

निष्कर्ष

अहमदाबाद में ग्राम–2026 निवेशक बैठक राजस्थान की कृषि के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कार्यक्रम निवेशकों, नव-उद्यमों, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाकर कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, दुग्ध और सहकारिता के लिए नई संभावनाएँ खोलेगा। यह राजस्थान को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और नवाचार-आधारित कृषि-प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने में मदद कर सकता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1: वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन (ग्राम)–2026 निवेशक बैठक किस शहर में आयोजित होगी?

a) जयपुर
b) अहमदाबाद
c) जोधपुर
d) उदयपुर

उत्तर: b) अहमदाबाद

व्याख्या: वैश्विक राजस्थान कृषि-प्रौद्योगिकी सम्मेलन (ग्राम)–2026 की निवेशक बैठक 30 अप्रैल को अहमदाबाद में आयोजित होगी। इसका ध्यान कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, दुग्ध और सहकारिता क्षेत्रों में निवेश तथा साझेदारी के अवसरों पर केंद्रित रहेगा।

प्रश्न 2: ग्राम–2026 निवेशक बैठक में मुख्य अतिथि कौन होंगे?

a) डॉ. किरोड़ी लाल
b) जोराराम कुमावत
c) भजनलाल शर्मा
d) मंजू राजपाल

उत्तर: c) भजनलाल शर्मा

RASonly

व्याख्या: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम–2026 निवेशक बैठक में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति राजस्थान के कृषि नवाचार और निवेश के लिए इस आयोजन के महत्व को दर्शाती है।

प्रश्न 3: मुख्य संवाद का विषय क्या होगा?

a) विरासत और पर्यटन
b) शहरी परिवहन और स्मार्ट शहर
c) पशुपालन, दुग्ध और सहकारिता में अवसर एवं निवेश संभावनाएँ
d) सौर ऊर्जा उद्यान

उत्तर: c) पशुपालन, दुग्ध और सहकारिता में अवसर एवं निवेश संभावनाएँ

व्याख्या: निवेशक बैठक में पशुपालन, दुग्ध और सहकारिता में अवसर एवं निवेश संभावनाओं पर संवाद आयोजित किया जाएगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान कृषि से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहता है और निवेश-अनुकूल ग्रामीण वातावरण बनाना चाहता है।

Rajasthan Census 2027 Campaign and Self-Enumeration Facility Starts from 16 May

Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma has urged the people of the state to be a part of Census 2027 and make it their constitutional and national responsibility. He said that the census is not just data, but also a national exercise that will help in defining the future of the country. The Rajasthan Census 2027 campaign will kick off in May with the first phase. The portal will also provide people with the option of

self-enumeration from 1 May to 15 May. The campaign is part of the Digital India campaign and leads to better governance through accurate data.

Rajasthan's Census 2027 Highlights

- Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma urged people to engage in Census 2027.
- The census, he said, is a constitutional and national obligation.
- Rajasthan has the largest geographical area in India.
- Census employees will cover a long distance to collect information.
- People have been asked to give correct, true and full information about houses and families.
- Rajasthan will start the first phase of Census 2027 in May.
- House listing and housing census will be done from 16 May to 14 June.
- Data will be collected from households by enumerators.
- People will also have the option of self-enumeration between 1 May and 15 May.
- Self-enumeration will be done through portal se.census.gov.in.

Self-Enumeration Facility

The self-enumeration facility is a significant initiative as part of the Digital India program. Between 1 May and 15 May, people can log onto the portal and provide their data. This will make the census more citizen-friendly and tech-savvy. The Chief Minister appealed to everyone to make use of this service and be part of this national exercise.

Significance of Census Data

Census information is a key resource for planning. Census data helps the Central and State Governments in formulating and implementing various welfare programs. It helps in getting information about the people and families of the villages and cities, the availability and need of electricity, water, roads, toilets, schools, hospitals and domestic gas.

Significance for Rajasthan

- The census will assist in knowing the socio-economic status of people and families.
- It will help in the development of villages and urban areas.
- It will assist the government to determine the need for basic services.
- It will enhance the delivery of government welfare programs.
- It will encourage evidence-based governance.
- It will promote people's participation in nation building.

RASonly

RAS Exam Relevance

This is important for RAS under the heads of governance, public administration, Rajasthan current affairs, Digital India, welfare planning and evidence-based policy making. Planning, allocation and implementation of government schemes are associated with census data. The self-enumeration option also reflects the growing digitisation in government.

Conclusion

The Rajasthan Census 2027 campaign is a significant contribution towards data collection and governance. When citizens give accurate data, it will help governments plan and implement development and welfare initiatives. The provision for self-enumeration from 1 May to 15 May and house listing work from 16 May to 14 June will empower citizens to be a part of this national process.

MCQs

MCQ 1: When will house listing and housing census be conducted in Rajasthan for Census 2027?

a) 1 May

b) 15 May

c) 16 May

d) 14 June

Answer: c) 16 May

Explanation : The Census 2027 in Rajasthan will start with the first phase in May. During this phase, house listing and house census will be done from 16 May to 14 June. House-to-house visits will be made to gather data on houses and families.

MCQ 2: Which website will be used to access Census 2027 self-enumeration?

a) rajcensus.gov.in

b) se.census.gov.in

c) censusrajasthan.in

d) digitalcensus.rajasthan.gov.in

Answer: b) se.census.gov.in

RASonly

Explanation: The facility of self-enumeration will be available to the citizen from 1 May to 15 May at the portal se.census.gov.in. This is part of the Digital India initiative and will make citizens active stakeholders of the Census.

MCQ 3: What are the uses of census data?

a) It is used only for election campaigns.

b) It is used in the design and planning of welfare programs.

c) It is used only for school admissions.

d) It is only used for maintaining records.

Answer : b) It is used for preparing and implementing welfare schemes.

Explanation: Census data helps in gathering information about population, households, and basic amenities like electricity, water, roads, toilets, schools, hospitals and domestic gas. This assists the Central and State Governments in developing and delivering effective welfare schemes.

राजस्थान जनगणना 2027 अभियान और स्व-गणना सुविधा 16 मई से शुरू होगा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से **जनगणना 2027** में भाग लेने और इसे अपना संवैधानिक तथा राष्ट्रीय दायित्व मानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय अभ्यास है, जो देश के भविष्य की दिशा तय करने में सहायक होगा। राजस्थान में जनगणना 2027 अभियान का पहला चरण मई में शुरू होगा। नागरिकों को 1 मई से 15 मई तक पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह अभियान डिजिटल इंडिया की भावना से जुड़ा है और सटीक आंकड़ों के आधार पर बेहतर शासन को बढ़ावा देता है।

राजस्थान जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएँ

• राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से जनगणना 2027 में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

• उन्होंने जनगणना को संवैधानिक और राष्ट्रीय दायित्व बताया।

• राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है।

• जनगणना कर्मचारी जानकारी एकत्र करने के लिए लंबी दूरी तय करेंगे।

• लोगों से मकानों और परिवारों के बारे में सही, सत्य और पूर्ण जानकारी देने की अपील की गई है।

• राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण मई में शुरू होगा।

• मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा।

RASonly

• प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

• लोगों को 1 मई से 15 मई के बीच स्व-गणना की सुविधा भी मिलेगी।

• स्व-गणना **se.census.gov.in** पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

स्व-गणना सुविधा

स्व-गणना सुविधा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। 1 मई से 15 मई के बीच नागरिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इससे जनगणना प्रक्रिया अधिक नागरिक-अनुकूल और तकनीक आधारित बनेगी। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस सुविधा का उपयोग करने और इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है।

जनगणना आंकड़ों का महत्व

जनगणना के आंकड़े योजना निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ये आंकड़े केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। इनके माध्यम से गांवों और शहरों के लोगों तथा परिवारों की स्थिति, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, विद्यालय, अस्पताल और घरेलू गैस की उपलब्धता तथा आवश्यकता के बारे में जानकारी मिलती है।

राजस्थान के लिए महत्व

• जनगणना लोगों और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने में सहायता करेगी।

• यह गांवों और शहरों के विकास में मदद करेगी।

• यह सरकार को मूलभूत सेवाओं की आवश्यकता निर्धारित करने में सहायता करेगी।

• यह सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को बेहतर बनाएगी।

• यह प्रमाण-आधारित शासन को प्रोत्साहित करेगी।

• यह राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा देगी।

RAS परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यह विषय RAS के लिए शासन, लोक प्रशासन, राजस्थान समसामयिकी, डिजिटल इंडिया, कल्याणकारी योजना निर्माण और प्रमाण-आधारित नीति निर्माण के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। जनगणना के आंकड़े योजना निर्माण, संसाधन आवंटन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े होते हैं। स्व-गणना सुविधा शासन में बढ़ते डिजिटलीकरण को भी दर्शाती है।

निष्कर्ष

राजस्थान जनगणना 2027 अभियान आंकड़ा संग्रह और बेहतर शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। जब नागरिक सटीक जानकारी देंगे, तो सरकारों को विकास और कल्याणकारी पहलों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने में सहायता मिलेगी। 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना सुविधा और 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण कार्य नागरिकों को इस राष्ट्रीय प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाएंगे।

RASonly

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1: जनगणना 2027 के लिए राजस्थान में मकान सूचीकरण और मकान गणना कब शुरू होगी?

a) 1 मई
b) 15 मई
c) 16 मई
d) 14 जून

उत्तर: c) 16 मई

व्याख्या: राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण मई में शुरू होगा। इस चरण के दौरान मकान सूचीकरण और मकान गणना का कार्य 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा। मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए घर-घर जाकर संपर्क किया जाएगा।

प्रश्न 2: जनगणना 2027 की स्व-गणना सुविधा के लिए किस वेबसाइट का उपयोग किया जाएगा?

a) rajcensus.gov.in
b) se.census.gov.in
c) censusrajasthan.in
d) digitalcensus.rajasthan.gov.in

उत्तर: b) se.census.gov.in

व्याख्या: नागरिकों को 1 मई से 15 मई तक se.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने में सहायक होगी।

प्रश्न 3: जनगणना आंकड़ों का उपयोग किसलिए किया जाता है?

a) यह केवल चुनाव अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है।
b) यह कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा और योजना बनाने में उपयोग किया जाता है।
c) यह केवल विद्यालय प्रवेश के लिए उपयोग किया जाता है।
d) यह केवल अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है।

उत्तर: b) यह कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा और योजना बनाने में उपयोग किया जाता है।

व्याख्या: जनगणना के आंकड़े जनसंख्या, परिवारों और बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, विद्यालय, अस्पताल तथा घरेलू गैस जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने में सहायता करते हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं बनाने और उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलती है।

RASonly

iStart and SMART in Rajasthan to drive Future-ready Innovation Ecosystem

The Department of Information Technology and Communication in Rajasthan has implemented the flagship iStart program and the SMART Project, which were reviewed by Rajasthan Chief Secretary V. Srinivas. The discussion was centred on improving Rajasthan's startup culture, innovation and entrepreneurship environment, and enhancing the delivery of public services through Artificial Intelligence and real-time digital platforms. These programs are relevant for RAS aspirants because they represent Rajasthan's commitment to innovation economy, smart governance, startups, job creation and citizen friendly public service delivery.

Review Highlights

- The Chief Secretary of Rajasthan, V. Srinivas, reviewed the iStart program.
- He acknowledged that iStart has been instrumental in building the startup and innovation eco-system.
- Rajasthan is looking at the new and emerging areas like Artificial Intelligence, Machine Learning, renewable energy, solar, agritech, rural innovation, AVGC-XR and the Orange Economy.
- iStart assists startups, innovators, students and entrepreneurs.
- It offers mentoring, incubation, market and investor connect, policy support and ecosystem partnerships.

- It promotes synergy between the government, industry, academia, incubators and innovation ecosystem.
- The Chief Secretary asked the department to intensify outreach and engagement with the ecosystem in Rajasthan.
- He stressed the need for frequent workshops, innovation clinics, mentoring and capacity-building programs.
- Startup Summits, investor connect programs, innovation challenges and themed workshops were also emphasised.

Focus on iStart Program

The iStart program is one of the major programs aimed at promoting the startup and entrepreneurship ecosystem in Rajasthan. This initiative seeks to institutionalise support to startups through mentoring, incubation, market linkages and investment opportunities. The Chief Secretary emphasised the need to improve the connection between the government departments, banks, incubators, universities and industry partners. He also emphasised the need to strengthen credit linkage programs to provide finance to startups at various growth levels.

Review of SMART Project

The Chief Secretary also discussed the SMART Project (Service Management with Artificial Intelligence and Real-Time System). The project seeks to revolutionise service delivery to citizens through proactive and technology-driven governance. Department of Information Technology and Communication officials briefed the meeting on the status, achievements and plans for the project.

SMART Project's Goals

- To apply Artificial Intelligence in public service delivery.
- To automatically select beneficiaries of government services.
- To eliminate the need for applications and timely payment of benefits.
- To enhance transparency, efficiency and people-friendly governance.
- To enable tech-enabled proactive delivery of services.

Instructions of Chief Secretary

- Improve co-ordination between concerned departments.
- Resolve inter-departmental problems and bottlenecks in a timely manner.
- Adhere to project schedules.
- Share the benefits of innovation ecosystem with grassroots innovators and startups.
- Highlight entrepreneurship success stories to motivate youth and ecosystem.
- Promote Rajasthan as a destination for startups and technology innovations through national and international innovation platforms.

RASonly

Significance for Rajasthan

- These programs can boost Rajasthan's innovation economy.
- They can provide sustainable economic opportunities and jobs.
- They can help the youth, students, startups and entrepreneurs.
- They can help make governance technology-enabled and digital.
- They can make Rajasthan a future-fit startup and tech hub.
- The SMART Project can speed up, transparency and user-friendly delivery of welfare.

RAS Exam Relevance

This can be a topic for RAS under Rajasthan current affairs, governance, public administration, e-governance, Artificial Intelligence, startups, entrepreneurship, employment generation and innovation-based development. The iStart program demonstrates the role of the government in promoting startups while the SMART Project represents the use of technology in active and citizen-friendly governance.

Conclusion

The analysis of iStart and SMART projects demonstrates Rajasthan's efforts to promote innovation and digital transformation. Whereas iStart is a program to enhance startups, entrepreneurship and innovation partnerships, the SMART Project is for delivering citizen services powered by Artificial Intelligence. These initiatives can help Rajasthan prepare for the future economy, and even build a smart governance model.

MCQs

MCQ 1: Chief Secretary V. Srinivas reviewed which flagship program to boost Rajasthan's startups and innovation?

a) PM-KUSUM

b) iStart program

c) Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan

d) Smart Cities Mission

Answer: b) iStart program

Explanation : Chief Secretary V. Srinivas discussed the Rajasthan government's iStart program launched by the Department of Information Technology and Communication. This program offers mentoring, incubation support, market access, investor connect, policy and ecosystem partners to startups, innovators, students and entrepreneurs.

RASonly

MCQ 2: What does SMART stand for in the Project reviewed by the Chief Secretary?

a) Startup Management with Real-Time Technology

b) Service Management using Artificial Intelligence and Real-Time System

c) Intelligent Monitoring for Agricultural Revolution and Technology

d) State Mission for Advanced Research and Training

Answer : b) Service Management with Artificial Intelligence and Real-Time System

Explanation : SMART Project is Service Management with Artificial Intelligence and Real-Time System. It seeks to revolutionise service delivery to citizens with the help of artificial intelligence and real-time electronic systems by automatically identifying the targeted beneficiaries and delivering government schemes and services to them on time.

MCQ 3: What is one of the objectives of the SMART Project?

a) To organise tourism fairs in Rajasthan

b) To personally check all applications for government schemes

c) To automatically select appropriate beneficiaries for government schemes

d) To encourage only renewable energy startups

Answer : c) To automatically identify beneficiaries for various government schemes

Explanation : The SMART Project is primarily aimed at automatically identifying beneficiaries for government schemes and services. This will make service delivery of benefits without manual applications seamless and timely and will increase accountability, efficiency and citizen-centric governance.

राजस्थान में भविष्य-उन्मुख नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आईस्टार्ट और स्मार्ट पहल

राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा लागू प्रमुख **आईस्टार्ट कार्यक्रम** और **स्मार्ट परियोजना** की समीक्षा राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की। चर्चा का केंद्र राजस्थान के नव-उद्यम, नवाचार और उद्यमिता वातावरण को मजबूत करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को बेहतर बनाना था। ये कार्यक्रम राजस्थानी प्रशासनिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं,

RASonly

क्योंकि ये राजस्थान की नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था, स्मार्ट शासन, नव-उद्यमों, रोजगार सृजन और नागरिक-अनुकूल सार्वजनिक सेवा आपूर्ति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

समीक्षा की मुख्य बातें

• राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने **आईस्टार्ट कार्यक्रम** की समीक्षा की।

• उन्होंने स्वीकार किया कि आईस्टार्ट ने नव-उद्यम और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

• राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अधिगम, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कृषि-प्रौद्योगिकी, ग्रामीण नवाचार, दृश्य-श्रव्य-क्रीड़ा-चित्रकला-विस्तारित वास्तविकता और नारंगी अर्थव्यवस्था जैसे नए एवं उभरते क्षेत्रों पर ध्यान दे रहा है।

• आईस्टार्ट नव-उद्यमों, नवाचारकर्ताओं, विद्यार्थियों और उद्यमियों की सहायता करता है।

• यह परामर्श, संवर्धन, बाजार संपर्क, निवेशक संपर्क, नीतिगत सहयोग और पारिस्थितिकी साझेदारी प्रदान करता है।

• यह सरकार, उद्योग, शिक्षा-जगत, संवर्धन केंद्रों और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच तालमेल को बढ़ावा देता है।

• मुख्य सचिव ने विभाग को राजस्थान में पारिस्थितिकी तंत्र के साथ पहुंच और सहभागिता को बढ़ाने के निर्देश दिए।

• उन्होंने नियमित कार्यशालाओं, नवाचार परामर्श शिविरों, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

• नव-उद्यम शिखर सम्मेलन, निवेशक संपर्क कार्यक्रम, नवाचार चुनौतियां और विषय-आधारित कार्यशालाओं पर भी जोर दिया गया।

आईस्टार्ट कार्यक्रम पर विशेष ध्यान

आईस्टार्ट कार्यक्रम राजस्थान में नव-उद्यम और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस पहल का उद्देश्य नव-उद्यमों को परामर्श, संवर्धन, बाजार संपर्क और निवेश अवसरों के माध्यम से संस्थागत सहायता प्रदान करना है। मुख्य सचिव ने सरकारी विभागों, बैंकों, संवर्धन केंद्रों, विश्वविद्यालयों और उद्योग भागीदारों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न विकास चरणों में नव-उद्यमों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण संपर्क कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई।

स्मार्ट परियोजना की समीक्षा

मुख्य सचिव ने **स्मार्ट परियोजना** पर भी चर्चा की। इसका पूरा नाम **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय प्रणाली के साथ सेवा प्रबंधन** है। यह परियोजना सक्रिय और तकनीक-आधारित शासन के माध्यम से नागरिक सेवा आपूर्ति में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखती है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के अधिकारियों ने बैठक में परियोजना की स्थिति, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी।

RASonly

स्मार्ट परियोजना के उद्देश्य

• सार्वजनिक सेवा आपूर्ति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना।

• सरकारी सेवाओं के लाभार्थियों का स्वतः चयन करना।

• आवेदन की आवश्यकता को समाप्त कर समय पर लाभ उपलब्ध कराना।

• पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-अनुकूल शासन को बढ़ाना।

• तकनीक-सक्षम सक्रिय सेवा आपूर्ति को संभव बनाना।

मुख्य सचिव के निर्देश

• संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

• विभागों के बीच समस्याओं और बाधाओं का समय पर समाधान किया जाए।

• परियोजना समय-सारणी का पालन किया जाए।

• नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ जमीनी स्तर के नवाचारकर्ताओं और नव-उद्यमों तक पहुंचाए जाएं।

• युवाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करने के लिए उद्यमिता की सफलता की कहानियों को प्रमुखता दी जाए।

• राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नवाचार मंचों के माध्यम से राजस्थान को नव-उद्यम और तकनीकी नवाचारों के केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाए।

राजस्थान के लिए महत्व

• ये कार्यक्रम राजस्थान की नवाचार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं।

• ये सतत आर्थिक अवसर और रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

• ये युवाओं, विद्यार्थियों, नव-उद्यमों और उद्यमियों की सहायता कर सकते हैं।

• ये शासन को तकनीक-सक्षम और डिजिटल बनाने में मदद कर सकते हैं।

• ये राजस्थान को भविष्य के अनुरूप नव-उद्यम और तकनीकी केंद्र बना सकते हैं।

• स्मार्ट परियोजना कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति को तेज, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बना सकती है।

राजस्थानी प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

यह विषय राजस्थान समसामयिकी, शासन, लोक प्रशासन, ई-शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नव-उद्यम, उद्यमिता, रोजगार सृजन और नवाचार-आधारित विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। आईस्टार्ट कार्यक्रम नव-उद्यमों को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका को दर्शाता है, जबकि स्मार्ट परियोजना सक्रिय और नागरिक-अनुकूल शासन में तकनीक के उपयोग को प्रस्तुत करती है।

RASonly

निष्कर्ष

आईस्टार्ट और स्मार्ट परियोजनाओं की समीक्षा राजस्थान में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाती है। आईस्टार्ट नव-उद्यमों, उद्यमिता और नवाचार साझेदारियों को मजबूत करने वाला कार्यक्रम है, जबकि स्मार्ट परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित नागरिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए है। ये पहल राजस्थान को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने और स्मार्ट शासन मॉडल विकसित करने में सहायता कर सकती हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान के नव-उद्यमों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस प्रमुख कार्यक्रम की समीक्षा की?

a) पीएम-कुसुम
b) आईस्टार्ट कार्यक्रम
c) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
d) स्मार्ट शहर मिशन

उत्तर: b) आईस्टार्ट कार्यक्रम

व्याख्या: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा संचालित राजस्थान सरकार के आईस्टार्ट कार्यक्रम की समीक्षा की। यह कार्यक्रम नव-उद्यमों, नवाचारकर्ताओं, विद्यार्थियों और उद्यमियों को परामर्श, संवर्धन सहायता, बाजार संपर्क, निवेशक संपर्क, नीतिगत सहायता और पारिस्थितिकी साझेदारी प्रदान करता है।

प्रश्न 2: मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की गई स्मार्ट परियोजना का पूरा नाम क्या है?

a) वास्तविक समय तकनीक के साथ नव-उद्यम प्रबंधन
b) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय प्रणाली के साथ सेवा प्रबंधन
c) कृषि क्रांति और तकनीक के लिए बुद्धिमान निगरानी
d) उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य मिशन

उत्तर: b) कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय प्रणाली के साथ सेवा प्रबंधन

व्याख्या: स्मार्ट परियोजना का पूरा नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय प्रणाली के साथ सेवा प्रबंधन है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय डिजिटल प्रणालियों की सहायता से लक्षित लाभार्थियों की स्वतः पहचान करके उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का समय पर लाभ पहुंचाते हुए नागरिक सेवा आपूर्ति में परिवर्तन लाना है।

प्रश्न 3: स्मार्ट परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?

a) राजस्थान में पर्यटन मेलों का आयोजन करना
b) सरकारी योजनाओं के सभी आवेदनों की व्यक्तिगत जांच करना
c) सरकारी योजनाओं के लिए उपयुक्त लाभार्थियों का स्वतः चयन करना
d) केवल नवीकरणीय ऊर्जा नव-उद्यमों को प्रोत्साहित करना

उत्तर: c) सरकारी योजनाओं के लिए उपयुक्त लाभार्थियों का स्वतः चयन करना

RASonly

व्याख्या: स्मार्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभार्थियों की स्वतः पहचान करना है। इससे बिना मैनुअल आवेदन के लाभों की सेवा आपूर्ति सहज और समयबद्ध हो सकेगी तथा शासन में जवाबदेही, दक्षता और नागरिक-केंद्रितता बढ़ेगी।

RASonly